

उत्तराखण्ड मेगा औद्योगिक एवं नविश नीति 2025

चर्चा में क्यों?

उत्तराखण्ड के [मुख्यमंत्री](#) पुष्कर सिंह धामी ने मेगा औद्योगिक और नविश नीति 2025 को मंजूरी दे दी है।

मुख्य बंदि

- नीति के बारे में:
 - इसे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूंजी नविश के लिये उत्तराखण्ड को एक प्रतिस्पर्धी गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लिये पेश किया गया है।
 - इसका उद्देश्य राज्य की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना तथा बड़े पैमाने पर वनिरिमाण उद्यमों को बढ़ावा देकर अतिरिक्त [रोज़गार](#) के अवसर सृजित करना है।
- पॉलिसी अवधि और पात्रता:
 - यह नीति पाँच वर्षों तक लागू रहेगी।
 - लाभ के लिये आवेदन करने वाले उद्यमों को सगिल वडिो पोर्टल के माध्यम से एक सामान्य आवेदन प्रपत्र (CAF) प्रस्तुत करना होगा।
 - वित्तीय प्रोत्साहन उद्यम की नविश श्रेणी के आधार पर दिया जाएगा।
 - नविश पूरा करने का समय CAF आवेदन की तारीख से 3 से 7 वर्षों के भीतर निर्धारित है।
- उद्यमों का वर्गीकरण:
 - बड़े उद्यमों को स्थायी पूंजी नविश (भूमि को छोड़कर) और न्यूनतम रोज़गार मानदंड के आधार पर चार श्रेणियों में वभिजति किया गया है।

वर्ग	नविश सीमा (रुपए)	न्यूनतम रोज़गार आवश्यक
लार्ज	50 करोड़ से 200 करोड़	50
अल्ट्रा लार्ज	200 करोड़ से 500 करोड़	150
मेगा	500 करोड़ से 1000 करोड़	300
अल्ट्रा मेगा	1000 करोड़ से अधिक	500

वित्तीय प्रोत्साहन:

- **स्टॉप ड्यूटी प्रतपूर्ति:** भूमि खरीद/लीज डीड पर चुकाई गई [स्टॉप ड्यूटी](#) का 50% तक प्रतपूर्ति, अधिकतम ₹50 लाख तक।
- **पूंजी सब्सिडी:** नविश श्रेणी के अनुसार, वाणजियिक उत्पादन शुरू होने के बाद वार्षिक कशितों में देय।
 - लार्ज: नविश का 10% 8 वर्षों के बाद
 - अल्ट्रा लार्ज: नविश का 12% 10 वर्षों के बाद
 - मेगा: नविश का 15% 12 वर्षों के बाद
 - अल्ट्रा मेगा: नविश का 20% 15 वर्षों के बाद
- **पहाड़ी क्शेत्रों के लिये अतिरिक्त सब्सिडी:**
 - श्रेणी A ज़िलों: पूंजी सब्सिडी में अतिरिक्त 2%
 - श्रेणी B ज़िलों: पूंजी सब्सिडी में अतिरिक्त 1%

